SHRI INDRAJIT GUPTA: I would like to know how many films are imported by us from USA every year under this new agreement and what will be the process for selection of films in order to ensure that films depicting certain aspects of the American way of life which may not have a very beneficial effect on the younger generation in our country are not allowed to come here?

SHRI DHARAM BIR SINHA: Under the agreement we can import between 100-150 films per year. The films to be imported are canalised through FFC, which selects the films which are to be imported. Other than this the imported films will have to go through censorship process and the films which we consider not to be good enough to be shown in India will not be allowed.

SHRI R. S PANDEY: I would like to know whether we stand in the world so far as this motion picture production is concerned? Secondly, what are those countries where our pictures are becoming very popular?

SHRI DHARAM BIR SINHA: Sir, I want a separate notice for this.

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी

+

*225. **श्री राज भगत पासवान :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी पर कुल कितना मासिक और वार्षिक व्यय किया जा रहा है ;

(ख) अब तक सरकार को राज्यवार कितने बोगस पेंशन पाने वालों का पता लग सका है और अन्य बोगस पेंशन पाने वालों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) उन बोगस राजनीतिक पेंशन पाने वालों में से कितनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है और कितनों को दंड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल टी 105/8/76]

श्री राज भगत पासवान फ्रीडम फायटर्स को पेंशन मिल रही है, इसके लिए तो श्रद्धा है, लेकिन बहुत से बोगस फ्रीडम फाइटर्स पेंशन ले रहे है, जो कभी आजादी की लड़ाई मे जेल नही गये। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो नियम निर्धारित किया है कि जिसकी कम-से-कम 3 हजार के अंदर सालाना आमदनी है और जो 6 महीने की सजा पाये हुए है, उनको पेंशन मिले, लेकिन सब लोगो को पेंशन मिल रही है जिनकी 20 से लेकर सैकड़ों एकड़ तक जमीन है और लाखो की प्रापर्टी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सही व्यक्तियों को पेंशन मिले और बोगस की कैंसिल हो जाये, क्या इसके लिये जिलेवार एक उच्च-स्तरीय कमेटी का निर्माण करेंगे जिससे सही का पता लग सके और बोगस लोगों की पेंशन बन्द हो सके और जो सरकारी धन का मिस-यूज हो रहा है, वह बन्द हो सके।

SHRI F. H. MOHSIN: It is not true that a large number of bogus freedom fighters are receiving pension. We received complaints in respect of 3430 cases and we suspended pension in the case of 2604. The number of cases disposed of: 21 plus 46 and then restored again 126. The number of cases which are pending is 3437. In order to find out whether a person is a bogus freedom fighter or not, as soon as we

receive the complaint from responsible persons we send the same to the State Government concerned for verification and the State Governments have their own committees. They make enquiries and send the report. If the State Government also says it is bogus then the pension is cancelled. In some cases State Governments have launched prosecutions also but it is not a fact to say that a large number of freedom fighters are bogus. There are nearly 1,10,000 freedom fighters who are getting pension and only 3430 complaints have been received and many of them may not be true. Mr. Paswan has suggested that district level committees should be made. That is not possible in a large country like ours. We send the complaints for verification to the State Governments and we depend on them for verification.

श्री राम भगत पासवान : कंप्लेंट की जांच करने का जो तरीका मंत्री महोदय ने बताया है वह स्टेट लैवल कमेटी है । स्टेट लैवल कमेटी स्वंय जांच नहीं करती है। वह उसे डिस्ट्रिक्ट में भेज देती है और डिस्ट्रिक्ट वी० डी० ओ० को भेज देता है, वी० डी० ओ० मुखिया जी के यहां भेज देता है । मुखिया जी फ्रीडम-फाइटर के हक में फेवरेबल रिपोर्ट दे देते हैं, और उसी माध्यम से रिपोर्ट उनके यहां आ जाती है । इस तरह से सचाई का पता नहीं लगता है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मुखिया जी के माध्यम से इन्क्वायरी न कराकर जेल सर्टिफिकेट के आधार पर इन्क्वायरी की जाये, और साथ ही उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई जाये ताकि सत्य का पता लग सके और पैंशन जैनुइन आदमियों को मिल सके, बोगस भी बन्द हो।

SHRI F. H. MOHSIN: A freedom fighter will be eligible for pension if he produces a jail certificate to show that he has suffered more than six months imprisonment or produces a certificate from a co-prisoner who is a sitting MP or MLA or ex-MP or ex-MLA showing that he was with him for more than six months. As regards bogus freedom fighters, wide publicity is given to persons who are getting pension. We have requested State Governments to see that they are printed in the local newspapers. We send our lists to the State Governments also. The District Collectors are required to publish it. Perhaps now due to paper shortage, they are not being published. But we have renewed our request to them to get them published.

As regards the complaint of Shri Paswan, it is about one particular case. Perhaps he would like to know about that . .

MR. SPEAKER: He should know, you need not reply to that.

श्री शंकर दयाल सिंह हम लोगों के सामने जो बयान आया है उसके अनुसार हमें 21 लोगों की सूची है, जिन्होंने गलत रूप से पैंशन ले लिया है और उनकी पैंशन रोकी गई है । मेरा कहना यह है कि जैसे जेलर या वारन्टर को भी किसी काम के लिये दोषी होना पड़ता है, वैसे ही जिन लोगों को पैंशन दी गई, उनको या तो जैल से सर्टिफिकेट मिले होंगे या उनके साथ जो राजनीतिक लोग रहे होंगे उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिये होंगे तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई या कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि ज्यादा जवाबदेही उनकी है ।

SHRI F. H. MOHSIN: I have stated that in 21 cases we have stopped pension because they were bogus. We have asked State Governments to consider the desirability of undertaking prosecution in 16 cases. About 5 cases are pending consideration of the Central Government.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: I am not talking about bogus freedom fighters, I am talking about persons who have given false certificates.

SHRI F. H. MOHSIN: It is very difficult to find out whether one has given a false certificate or not. They are considered to be responsible persons—MPs, MLAs, ex-MPs and ex-MLAs; Many sitting MPs have given certificates. If we were to hold an inquiry into each and every case, members themselves may not think it desirable.

I may point out that in the initial stage when the Central scheme came into force, only jail certificates were accepted. Then we found that in some cases, jail certificates were not available. The Prime Minister then desired that this condition might be relaxed and we could accept certificates from MPs, MLAs, sitting ex-MPs or ex-MLAs. We have to reply on these certificates. We cannot say that everybody is dishonest.

As regards finding out bogus freedom fighters, we want information from the public If they give information, we can act accordingly.

श्री डी० एन० तिवारी : अध्यक्ष जी, बोगस फ्रीडम-फाइटर कहना गलत है। फ्रीडम-फाइटर बोगस नही होता है यह कह सकते है कि बोगस लोगो ने पेंशन ले लिया है।

मै यह जानना चाहता हूं कि अभी तक जो आपने पेंशन दी है, उसके अलावा और कितने केसेस अभी डिस्पोज आफ करने के लिए बाकी रह गए है और उनमे से जल्दी डिस्पोज आफ करने मे क्या कठिनाई हो रही है। क्योंकि जो लोग पेंशन पा चुके है, वे निश्चिन्त है और जिनकी इन्क्वायरी हो रही है वे अपनी बात जानेगे, लेकिन दो तीन और चार वर्ष मे जो लोग अटके हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे है, जिससे वह केसेज जल्दी डिस्पोज आफ हो जाएं ?

SHRI F. H. MOHSIN: I will give the figures. The number of applications received within the due date 31-3-74 was 1,94,272. The number received after due date was 43,610. The total comes to 2,37,882. Out of that, 1,09,230 have been sanctioned; 9,908 have been rejected; 48,677 have been filed and only 67 are pending.

श्रीमती सहोदराबाई राय : जो लोग स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में ऐसी बाते कहते हैं अंग्रेजी शासन के समय तो उनका जन्म भी नही हुआ था। माननीय सदस्य ने उल्टी बात कही है कि स्वतन्त्रता सेनानी बोगस है और इस लिए उनको पेंशन नही मिलनी चाहिए। स्वतन्त्रता आन्दोलन के सिलसिले में कोई व्यक्ति चार महीने के लिए, कोई दो महीने के लिए और कोई एक महीने के लिए जेल में रहा। बहुत थोडे से लोग छः महीने के लिए जेल में गए। अब बहुत स्वतन्त्रता सेनानी बचे है, लेकिन माननीय सदस्य उनको पेंशन देने का विरोध करते है। कई बार ऐसा होता था कि लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरे गाव मे चले जाते थे। लेकिन उन लोगों ने भी काम किया था और इस लिए उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। यह जो छः महीने का नियम रखा गया है। वह गलत है और सोच समझ कर नही रखा गया है। छः महीने से कम समय के लिए जेल जाने वालों की भी स्वतन्त्रता सेनानियों की श्रेणी मे रखना चाहिए। पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्रता सेनानी को जेल से फार्म ला कर भरना पडता है और फिर कलेक्टर तथा प्रदेश सरकार द्वारा उस की इनक्वायरी होती है, जिस मे बहुत समय लग जाता है। मै यह जानना चाहती हूं कि सरकार क्या उपाय कर रही है, जिससे स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन जल्दी मिल जाए।

SHRI F. H. MOHSIN: We are giving pension even to persons who got a remission of one month, if they remained

in jail for five months and got one month's remission, they are eligible. If there was an arrest warrant and they were absconding or worked under ground they are eligible for pension provided they were working underground for more than six months.

श्री भाग सिंह कौरा : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन केसिज की जांच करने के लिए स्टेट लेवल पर कमेटिया बनाई गई है। वे कमेटियां कहती हैं कि अगर कुछ लोग गलत सर्टिफिकेट ले आए, तो हम उस में क्या कर सकते हैं। इसलिए वे कमेटियां इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दे सकती हैं। यह भी पता चला है कि कुछ क्रिमिनल्ज ने भी जेल जांच के गलत सर्टिफिकेट ले लिए और उन को भी पेंशन मिल गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सैंटर से कोई आदमी स्टेट्स में भेजा जाएगा, जो इस बात की जांच करे कि कौन कौन वाकई फ्रीडम फाइटर हैं। ये सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं, इसलिए वे तो उनको डिफेंड करेंगे ही। क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि कई आदमियों ने सौ दो सौ सर्टिफिकेट दिए हैं; अगर हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

SHRI F. H. MOHSIN: We depend upon the MPs and MLAs and other social workers also for bringing out such persons. The Punjab Government have connstituted a committee to find out such persons who will get pension who are not genuine freedom fighters but who are getting pension. Even in Assam a committee has been constituted by the state government to go into this because there are so many complaints from Cachar district and elsewhere. I should request the state governments to formulate committees for this purpose, wherever necessary.

MR. SPEAKER: Next question.

SHRI BHOGENDRA JHA: The way the question has been answered, it is very slanderous. I do not think it is the fact.... (*Interruptions*)

यह तो एक तरह से स्लैंडर हो गया है। इस लिए इस पर और क्वेस्चन करने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला सवाल पूछने के लिए कह दिया है।

Levy to raise Funds for Research and Development

+

*226. SHRI SAMAR MUKHERJEE:
SHRI DHAMANKAR:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government are having any proposal to impose a certain percentage as levy on the turnover or the profits of the industries to raise funds for research and development; and

(b) if so, salient features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI I K. GUJRAL): (a) Yes Sir, Government intend to levy a cess on industries under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, with a view to raise funds for research and development.

(b) The details of the scheme are being worked out and necesasry legislation in this behalf will be introduced in the Parliament soon.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: It appears in newspapers some weeks ago that some levy has been imposed on the jute industry recently for research and development work. I want to know which industries have been covered by this and in which of them a levy has been imposed and what type of research and development work is now done? Is it the purpose to have some diversification in the industry which is facing acute crisis now or is it to reduce the cost of production